

प्रेषक,

डा० अजय कुमार प्रद्योत,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
खेल निदेशालय,  
उत्तराखण्ड।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग -2

देहरादून दिनांक : 26 फरवरी, 2013

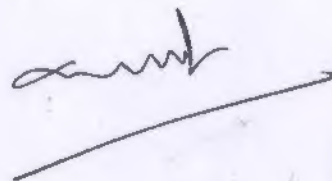
विषय :- जनपद देहरादून में मोरवियन स्कूल के निकट थानी ग्राम में निर्माणाधीन सिविल सर्विसेस इन्स्टीट्यूट के नवनिर्मित भवन के फर्नीसिंग कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1396/सि०सर्वि०पत्रा०/2012-13 दिनांक-21 जनवरी, 2013, शासनादेश संख्या-326/VI-2/2011-4(5)/2004, दिनांक-29 मार्च, 2011, शासनादेश संख्या-533/VI-2/2011-4(5)/2004, दिनांक 05 नवम्बर, 2012 तथा पत्र संख्या-39/VI-2/2011-4(5)/2004, दिनांक 06 फरवरी, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून में सिविल सर्विसेस इन्स्टीट्यूट के नवनिर्मित भवन के फर्नीसिंग कार्य हेतु ₹305.04 लाख (अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कार्यवाही करने हेतु) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष ₹81.45 लाख (इक्क्यासी लाख पैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2012-13 में आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- फर्नीसिंग कार्यों के लिए समस्त अधिप्राप्ति की मदों के सम्बन्ध में भिव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए कय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ही धनराशि आहरित/व्यय की जायेगी। अग्रेत्तर, उक्तानुसार कृत कार्यवाही के आधार पर वास्तविक देय धनराशि (मदवार कय हेतु नियमानुसार निर्धारित एल-1 दरों के अनुसार) की ही स्वीकृति प्रस्तावित की जायेगी। अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कृत कार्यवाही (एल-1 के निर्धारण विषयक) से सम्बन्धित प्रपत्र भी शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश सं०-475/XXVII(7)/2008 दिनांक-15-12-2008, 414/XXVII (7)/2007 दिनांक 23-10-2008 एवं सं०-594/XXVII





- (7)/2010 दिनांक-9-6-2010 के अनुसार MOU गठित कर Bsr-chart/Pert-chart के अनुरूप उक्तानुसार समय से निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायें। निर्माण कार्यों का गहन अनुश्रवण किया जाये।
- 3- कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय।
- 4- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
- 5- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219 (2006) दि0-30-6-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- 6- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-00-03-खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम-102-खेलकूद स्टेडियम-06-सिविल सर्विसेज संस्थान की स्थापना-24 वृहत निर्माण कार्य आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।
- 7- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-216(P)/XXVII (3)/2012-13 दिनांक-18 फरवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

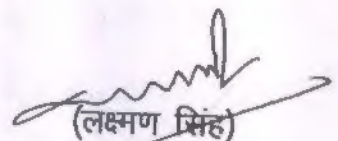
(डा० अजय कुमार प्रद्योत)  
सचिव

पृष्ठांकन संख्या- 60 /VI-2/2013-4(5) 2004 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी-1/105 इन्दिरा नगर, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम, देहरादून।
4. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
- ✓ 5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड देहरादून।
- ✓ 6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- ✓ 7. एन०आई०सी० देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(लक्ष्मण सिंह)  
अनुसचिव